

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (UCC)

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखण्ड में जल्द ही **समान नागरिक संहिता (UCC)** लागू की जाएगी।

- UCC लागू करने का बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मुख्य बंदि:

- UCC की परकिलपना पूरे देश के लयि एक सामान कानून प्रदान करने की है, जो सभी धारमकि समुदायों पर उनके व्यक्तगित मामलों जैसे वविह, तलाक, वरिसत, गोद लेने आदिपर लागू होगा।
- संवधान के **अनुच्छेद 44 अनुसार** राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लयि **एक समान नागरिक संहिता** सुनश्चिति करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद 44 **राज्य के नीत निदिशक सिदिधांतों (DPSP)** में से एक है।
 - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संवधान की प्रस्तावना में नहिति "**धरमनरिपेक्ष लोकतांत्रकि गणराज्य**" के उद्देश्य को मज़बूत करना है।
- गोवा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है।





UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption

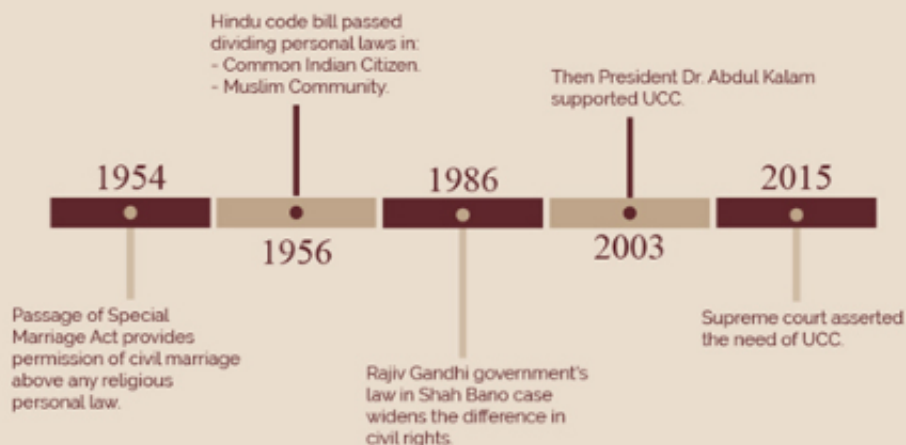


Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."
Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016